

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 986/2022

1. महेन्द्र कुमार जाट पुत्र श्री कल्याण मल, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी गाँव अकोदिया, पोस्ट संधली, तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)
2. लक्ष्मण फर्रोदा पुत्र श्री राम निवास, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी मुख्यबास, गाँव गाजू, जिला नागौर (राज.)
3. कुलदीप शर्मा पुत्र श्री रमेश चंद शर्मा, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी गाँव डोबला खुर्द, पोस्ट गांगल्यावास, तहसील रामगढ़, पचवारा, जिला दौसा (राज.)
4. मनीष कुमार नागर पुत्र श्री धनराज नागर, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी गाँव और पोस्ट कातावर, तहसील अटरू, जिला बारां (राज.)
5. नरेंद्र मेघवाल पुत्र श्री नाना लाल, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी 11/112, नाकोड़ा नगर, धुलजी की बावरी, देवारी रोड, जिला उदयपुर (राज.)
6. हेत राम गोदारा पुत्र श्री रुघा राम गोदारा, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी गाँव और पोस्ट सूरनाना, तहसील लूणकरनसर, जिला बीकानेर (राज.)

----अपीलकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके सचिव, राजस्व विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।

2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. कपिल कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश चंद शर्मा, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी गाँव डांगरवाड़ा, पोस्ट श्रीचंदपुरा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर (राज.)
5. मनोज कुमार डागुर पुत्र श्री विजय सिंह डागुर, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी गाँव और पोस्ट खेड़ी हैवत, तहसील हिंडौनसिटी, जिला करौली (राज.)
6. हरिओम सिंह गुर्जर पुत्र श्री गिराज प्रसाद गुर्जर, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी गाँव मुरलीपुरा, पोस्ट पंचोली, तहसील सिकराय, जिला दौसा (राज.)
7. कल्पित शर्मा, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी गाँव और पोस्ट कोलाना बांदीकुई, तहसील बासवा, जिला दौसा (राज.)
8. लाल चंद जाखड़ पुत्र श्री गणपत राम, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी 182, वार्ड नंबर 03, मंदिर की गुवार, तेजरासर, बीकानेर (राज.)
9. मनीष कुमार सेजू पुत्र श्री जगजीवन राम, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी संधावा, फतेहगढ़, जिला जैसलमेर (राज.)
10. कन्हैया लाल चौधरी पुत्र श्री राज लाल चौधरी, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी गाँव खलीलपुरा पापड़ा, पोस्ट बमोर, जिला टोंक (राज.)

11. मनफूल सिंह सारण पुत्र श्री जीत राम सारण, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी चक-39, एलएनपी कॉलोनी, पी.ओ. बाईझबायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर (राज.)
12. प्रवीण कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी गाँव ढाणी पूनिया, पोस्ट झरसासर छोटा, तहसील तारानगर, जिला चूरू (राज.)
13. प्रकाश जांडू पुत्र श्री बक्शा राम, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी जनेवा ईस्ट, गाँव और पोस्ट जनेवा ईस्ट, जिला नागौर (राज.)
14. कैलाश पुत्र श्री राजुराम, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी गाँव और पोस्ट फर्रोद, तहसील जायल, जिला नागौर (राज.)
15. निलेश कटारा पुत्र श्री वारसिंह, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी गाँव कुशालीपाड़ा, पोस्ट जलिमपुरा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

----प्रतिवादी

साथ में

(2) डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 782/2022

1. प्रकाश विश्वोई पुत्र श्री पुखराज, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी विश्वोईयो का बास, बिसलपुर, जिला जोधपुर (राजस्थान)
2. कृष्णकांत शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी विरहटा, खुंडा, जिला करौली (राजस्थान)

----अपीलकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्व विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. सचिव, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
3. अध्यक्ष, राजस्थान सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान)
4. प्रेमा राम पुत्र श्री शंकरा राम, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी जानियो की ढाणियां, रामसर, करनू, जिला नागौर (राजस्थान)
5. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री डोला राम, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी कमेड़िया का बास, खेड़ा किशनपुरा, जिला नागौर (राजस्थान)
6. आशीष कुमार शर्मा पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी देवनगर, बानसूर, अलवर (राजस्थान)
7. हेमराम पुत्र श्री बजरंग लाल, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी शेखपुरा, रियान बड़ी, जिला नागौर (राजस्थान)

-----प्रतिवादी

अपीलकर्ता के लिए : श्री जे.एम. सक्सेना, अधिवक्ता के साथ

श्री संजीव कुमार सिंघल, अधिवक्ता

श्री विशाल राज मेहता, अधिवक्ता और

सुश्री वंदना, अधिवक्ता

श्री चैतन्य कुमार गहलोत, अधिवक्ता

की ओर से वीसी के माध्यम से

प्रतिवादी के लिए : श्री नलिन जी. नारायण, अधिवक्ता

श्री राजेश महर्षि, एएजी,

श्री उदित शर्मा, अधिवक्ता, सहायक

श्री सुनील बेनीवाल, एएजी वीसी से

श्री विनीत सनाढ्य, अधिवक्ता वीसी के
माध्यम से

श्री तनांजय परमार, अधिवक्ता
वीसी के माध्यम से

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति शुभा मेहता

(वी.सी. के माध्यम से)

निर्णय

घोषित तिथि

::

10/07/2024

रिपोर्ट करने योग्य

न्यायालय द्वारा: (प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश)

- यह आदेश उपरोक्त दो अंतर-न्यायालय अपीलों के निपटान को नियंत्रित करेगा।
- डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 782/2022, इस न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में दायर की गई, जो अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका सहित रिट याचिकाओं के एक बैच में पारित दिनांक 27.05.2022 के एक सामान्य आदेश से उत्पन्न होती है।

डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 986/2022, जयपुर पीठ, जयपुर में दायर की गई, जो अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका सहित रिट याचिकाओं के एक बैच में पारित दिनांक 19.07.2022 के एक सामान्य आदेश से उत्पन्न होती है।

- दोनों अपीलों को जयपुर पीठ, जयपुर में एक साथ सुना गया।

4. राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित) द्वारा पटवारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए 17.01.2020 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित प्रतियोगी परीक्षा 23.10.2021 को आयोजित की गई थी और 23.10.2021 को ही बोर्ड द्वारा एक प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की गई थी जिसमें प्रारंभिक उत्तर कुंजी के प्रति ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। बोर्ड द्वारा 25.01.2022 को विशेषज्ञ समिति के निर्णय के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई थी, जो बोर्ड द्वारा प्रस्तावित उत्तर कुंजी के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों पर आधारित थी। इसके बाद चयनित सूची का प्रकाशन हुआ।

5. इस स्तर पर, अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी-अपनी रिट याचिकाएँ जोधपुर में प्रधान पीठ के साथ-साथ जयपुर में पीठ में दायर कीं, जिसमें विशेषज्ञ समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर प्रश्नचिह्न लगाया गया, जो विशेषज्ञ समिति द्वारा तय की गई उत्तर कुंजी की शुद्धता के संबंध में था। माननीय एकल न्यायाधीश ने जोधपुर में प्रधान पीठ में दायर रिट याचिकाओं पर निर्णय लेते हुए, दिनांक 27.05.2022 के आदेश के माध्यम से, विभिन्न प्रश्नों की उत्तर कुंजी की शुद्धता से संबंधित मुद्दे की जांच की। उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज-104D के प्रश्न संख्या 69 और 98 को छोड़कर, जिसमें क्वेश्चन बुकलेट सीरीज-104D के प्रश्न संख्या 98 के लिए, बोर्ड द्वारा दी गई रियायत के आधार पर, उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई कोई भी आपत्ति हस्तक्षेप के मापदंडों के भीतर नहीं आती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्धारित किया गया है, और इसलिए, यह माना कि दो प्रश्नों को छोड़कर, हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है। याचिकाओं को

तदनुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। हालांकि, अपीलकर्ता-प्रकाश विश्वाई और एक अन्य (डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 782/2022), क्वेश्चन बुकलेट सीरीज-104 सी के प्रश्न संख्या 135 की उत्तर कुंजी की शुद्धता के संबंध में आदेश से व्यथित महसूस कर रहे थे और उन्होंने अंतर-न्यायालय अपील दायर की।

6. चूंकि अपीलकर्ता-महेंद्र कुमार जाट (डीबीएसएडब्ल्यू संख्या 986/2022) और अन्य याचिकाओं की रिट याचिका सहित याचिकाओं के एक बैच को जयपुर पीठ, जयपुर में एक एकल पीठ द्वारा दिनांक 19.07.2022 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जो एक समान मुद्दे से संबंधित याचिकाओं के दूसरे बैच में जोधपुर में प्रधान पीठ में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के आलोक में था, इसलिए महेंद्र कुमार जाट द्वारा यह अपील भी दायर की गई है।

7. दोनों अपीलों में, इस न्यायालय के विचार के लिए केवल एक ही प्रश्न उठता है कि क्या माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज-104 सी के प्रश्न संख्या 135 की सही उत्तर कुंजी के संबंध में विशेषज्ञ समिति का निर्णय, हस्तक्षेप की वारंटी देता है। दोनों अपीलों में पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा तर्कों के दौरान कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया था।

8. क्वेश्चन बुकलेट सीरीज-104 सी का प्रश्न संख्या 135 नीचे दिया गया है:-

“135. ‘संत पीपा’ की गुफा कहाँ है?

(ए) पीपर

(बी) टोडा

(सी) धनेरा

(डी) गागरोन”

9. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जब बोर्ड द्वारा प्रारंभिक उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी, तो विकल्प "(बी) टोडा" को सही उत्तर कुंजी के रूप में चिह्नित किया गया था। हालांकि, जब विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा उत्तर कुंजी की शुद्धता के संबंध में आपत्तियां उठाई गईं, जिन्होंने दावा किया कि सही उत्तर कुंजी विकल्प "(डी) गागरोन" थी, तो बोर्ड ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया और अन्य प्रश्नों की उत्तर कुंजी की शुद्धता पर आपत्ति के साथ-साथ प्रश्न संख्या 135 के संबंध में इस आपत्ति को संदर्भित किया। यह भी विवाद में नहीं है कि विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न आपत्तियों पर विचार करने के बाद, उत्तर कुंजी को विकल्प "(बी) टोडा" से विकल्प "(डी) गागरोन" में बदल दिया।

10. अपीलकर्ता-प्रकाश विश्वाई और अन्य के मामले में माननीय एकल न्यायाधीश ने, विशेषज्ञ समिति के दृष्टिकोण पर भरोसा करते हुए, आपत्तियों को खारिज कर दिया। इस संबंध में, माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष नीचे उद्धृत किया गया है:-

“विशेषज्ञ समिति का दृष्टिकोण: विशेषज्ञ समिति ने राजस्थान का इतिहास और संस्कृति कक्षा 10 और राजस्थान-इतिहास और संस्कृति एनसाइक्लोपीडिया डॉ. हुकमचंद जैन और नारायण माली द्वारा लिखित का संदर्भ देते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सही उत्तर (डी) है।

हालांकि याचिकाकर्ताओं ने भी अपने तर्कों के समर्थन में कुछ सामग्री रिकॉर्ड पर रखी है कि उत्तर "बी" सही है, हालांकि, चूंकि विशेषज्ञ समिति ने, जैसा कि यहां पहले बताया गया है, और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री को ध्यान में रखते हुए,

एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंची है, इस न्यायालय के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करने का स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं है।"

11. दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वकीलों ने सामान्य प्रस्तुतियाँ दीं। रिकॉर्ड पर रखी गई विभिन्न सामग्रियों का जिक्र करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि जब विभिन्न प्रामाणिक ग्रंथों में यह दर्ज किया गया था कि संत पीपा की गुफा टोडा में थी, तो विशेषज्ञों की समिति ने इसे अनदेखा कर दिया और किसी भी प्रामाणिक सामग्री/ग्रंथों के बिना, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संत पीपा की गुफा गागरोन में स्थित है।

12. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि हालांकि शुरू में "टोडा" को सही उत्तर कुंजी के रूप में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन जब विभिन्न आपत्तियां उठाई गईं और कुछ उम्मीदवारों ने दावा किया कि संत पीपा की गुफा गागरोन में है, तो मामले को विशेषज्ञों की एक समिति को संदर्भित किया गया था और विशेषज्ञों की समिति ने विभिन्न ग्रंथों और आपत्तियों को ध्यान में रखने के बाद, अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि विकल्प "(डी) गागरोन" को सही उत्तर कुंजी के रूप में माना जाना चाहिए।

13. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने अपने तर्कों के समर्थन में विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है।

14. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील यह तर्क देंगे कि हालांकि न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है, वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम रूप से तय की गई उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से गलत है, जो विभिन्न ग्रंथों, सूचनाओं और सामग्रियों की सामग्री से परिलक्षित होती है, जो अपीलकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं।

प्रतिवादियों के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत सीमित है और इस न्यायालय को पुनर्-मूल्यांकन के किसी भी अभ्यास में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और न ही किसी दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो सकता है, इस पर अपनी राय को प्रतिस्थापित करना चाहिए, सिवाय बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों के जहां बिना किसी विस्तृत तर्क की प्रक्रिया के, उत्तर कुंजी को स्पष्ट रूप से गलत साबित कर दिया जाता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित किया गया है।

15. इससे पहले कि हम मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर गौर करें, प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उत्तर कुंजी की शुद्धता को चुनौती देने के मामले में न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में मुद्दे पर प्रसिद्ध निर्णयों का उल्लेख करना उपयोगी है।

16. शुरुआत में, यह अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है कि पुनर्-मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, कानून में उत्तरों का पुनर्-मूल्यांकन अनुमेय नहीं है, जैसा कि कई निर्णयों में माना गया है।

17. इस संबंध में स्थापित कानूनी स्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने **हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर और एक अन्य, (2010) 6 एससीसी 759** के मामले में दोहराया था और इसे नीचे दिए गए अनुसार माना गया था:-

"24. उत्तर पुस्तिका के पुनर्पुनर्-मूल्यांकन का मुद्दा अब कोई नई बात नहीं है। इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमारशेठ में विस्तार से विचार किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि

पुनर्-मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, इस प्रभाव के लिए एक निर्देश न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे माना कि नियमों/विनियमों में शामिल नीतिगत निर्णय भी जो पुनः जांच/सत्यापन/पुनर्-मूल्यांकन के लिए प्रदान नहीं करते हैं, को चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक कि यह दिखाने के लिए कोई आधार न हो कि नीति स्वयं कुछ वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने नीचे दिए गए अनुसार माना:

(एससीसी पृष्ठ 39-40 और 42, पैरा 14 और 16)

"14. ... यह विशेष रूप से विधायिका और उसके प्रतिनिधि के प्रांत के भीतर है, एक नीति के मामले के रूप में, यह निर्धारित करने के लिए कि कानून के प्रावधानों को सबसे अच्छी तरह से कैसे लागू किया जा सकता है और कानून के उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्रभावी उपलब्धि के लिए नियमों या विनियमों में कौन से उपाय, वास्तविक और साथ ही प्रक्रियात्मक, को शामिल किया जाना होगा ...

16. ... न्यायालय विधायिका और अधीनस्थ विनियमन-बनाने वाले निकाय द्वारा विकसित नीति की बुद्धिमत्ता पर निर्णय नहीं दे सकता है। यह एक बुद्धिमान नीति हो सकती है जो पूरी तरह से कानून के उद्देश्य को प्रभावित करेगी या यह प्रभावशीलता में कमी हो सकती है और इसलिए संशोधन और सुधार की मांग कर सकती है। लेकिन किसी नियम या विनियमन में शामिल नीति में कोई भी कमी इसे अल्ट्रा वायर्स नहीं बनाएगी और न्यायालय इसे इस आधार पर रद्द नहीं कर

सकता है कि, उसकी राय में, यह एक बुद्धिमान या विवेकपूर्ण नीति नहीं है, बल्कि एक मूर्खतापूर्ण भी है, और यह वास्तव में कानून के उद्देश्यों की सेवा नहीं करेगा "

25. इस दृष्टिकोण को प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित और relied upon और re-iterated किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है: (एससीसी पृष्ठ 717-18, पैरा 7)

"7. ... आयोग के प्रासंगिक नियमों के तहत, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कोई उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्-मूल्यांकन के लिए पूछने का हकदार हो। केवल जांच के लिए एक प्रावधान है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को यह जांचने के उद्देश्य से देखा जाता है कि क्या किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए सभी उत्तरों की जांच की गई है और क्या प्रत्येक प्रश्न के अंकों को कुल करने और उन्हें उत्तर पुस्तिका के पहले कवर पृष्ठ पर सही ढंग से नोट करने में कोई गलती हुई है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जांच के बाद सामान्य विज्ञान के पेपर में अपीलकर्ता को दिए गए अंकों में कोई गलती नहीं पाई गई। प्रासंगिक नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्-मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, किसी परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार को अपने अंकों के पुनर्-मूल्यांकन का दावा करने या पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

(जोर दिया गया)

इसी तरह का दृष्टिकोण मुनीब उल रहमान हारून (डॉ.) बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम डी. सुवंकर, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अयान दास और साहती बनाम डॉ. एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में दोहराया गया है।

26. इस प्रकार, इस विषय पर कानून इस प्रभाव से उभरता है कि कानून या वैधानिक नियमों/विनियमों के तहत किसी भी प्रावधान के अभाव में, न्यायालय को आम तौर पर पुनर्-मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए।"

18. उपरोक्त कानूनी स्थिति को **रण विजय सिंह और अन्य (supra)** और **हाईकोर्ट ऑफ त्रिपुरा, रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी और अन्य, (2019) 16 SCC 663** के मामलों में और पुष्ट किया गया है।

19. हालांकि, एक ऐसी स्थिति जहां स्वयं मुख्य उत्तर गलत पाए जाते हैं, जिसके लिए आवश्यक सुधार की आवश्यकता होती है, पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया गया है।

कानपुर विश्वविद्यालय, **कुलपति और अन्य के माध्यम से (supra)** के मामले में, कुछ प्रश्नों के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ कि उन प्रश्नों के लिए मुख्य उत्तर सही नहीं थे। तथ्यों पर, प्रामाणिक ग्रंथों की जांच पर, यह माना गया कि स्वयं मुख्य उत्तर सही नहीं थे। उच्च न्यायालय ने विशेष प्रश्नों के पुनः मूल्यांकन के लिए निर्देश जारी किया। ऐसे निर्देश की पुष्टि की गई। यह माना गया कि यदि संदेह का मामला है, तो पहले से ही प्रदान किए

गए मुख्य उत्तरों का पालन करना होगा, लेकिन यदि मामला संदेह के दायरे से परे है, तो छात्रों को एक ऐसा उत्तर नहीं देने के लिए दंडित करना अनुचित होगा जो मुख्य उत्तर के अनुरूप हो, जो गलत साबित होता है। यह महत्वपूर्ण रूप से देखा गया था:-

"15. उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से छात्र समुदाय के लिए बहुत महत्व का एक प्रश्न उठता है। आम तौर पर, एक व्यक्ति इस विचार की ओर झुकाव महसूस करता है, खासकर यदि वह एक पेपर सेटर और परीक्षक रहा हो, कि पेपर सेटर द्वारा दिए गए और विश्वविद्यालय द्वारा सही माने गए कुंजी उत्तर को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसे प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि मुख्य उत्तर को बिल्कुल भी प्रकाशित न किया जाए। यदि विश्वविद्यालय ने परीक्षा के परिणाम के साथ मुख्य उत्तर प्रकाशित नहीं किया होता, तो इस मामले में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यह उन मामलों को देखने का एक सही तरीका नहीं है जिसमें सैकड़ों छात्रों का भविष्य शामिल है जो पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आकांक्षी हैं। यदि इस मामले में मुख्य उत्तर को गुप्त रखा गया होता, तो उपाय बीमारी से भी बदतर होता क्योंकि, इतने सारे छात्रों को चुपचाप अन्याय सहना पड़ता। मुख्य उत्तर के प्रकाशन ने मामलों की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को उजागर किया है जिसका समाधान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को खोजना चाहिए। मुख्य उत्तर प्रकाशित करने में उनकी निष्पक्षता की भावना ने उन्हें उन परीक्षाओं की प्रणाली पर करीब से

देखने का अवसर दिया है जो वे आयोजित करते हैं। जो विफल हुआ है वह कंप्यूटर नहीं है बल्कि मानवीय प्रणाली है।

16. श्री कक्कड़, जो विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित होते हैं, ने तर्क दिया कि किसी भी मुख्य उत्तर की शुद्धता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि, उसके चेहरे पर, वह गलत न हो। हम सहमत हैं कि कुंजी-उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि वह गलत साबित न हो जाए और उसे तर्क की अनुमानित प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से गलत साबित किया जाना चाहिए, यानी, यह ऐसा होना चाहिए कि विशेष विषय में अच्छी तरह से वाकिफ पुरुषों का कोई भी उचित समूह इसे सही नहीं मानेगा। विश्वविद्यालय का तर्क इस मामले में बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों द्वारा झूठा साबित होता है, जिन्हें आमतौर पर यूपी में छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। वे पाठ्यपुस्तकों छात्रों के मामले का पूरी तरह से समर्थन करती हैं। यदि यह संदेह का मामला होता, तो हम निस्संदेह मुख्य उत्तर को पसंद करते। लेकिन यदि मामला संदेह के दायरे से परे है, तो छात्रों को एक ऐसा उत्तर नहीं देने के लिए दंडित करना अनुचित होगा जो मुख्य उत्तर के अनुरूप हो, यानी, एक ऐसे उत्तर के साथ जो गलत साबित होता है।"

20. एक अन्य मामले में, **मनीष उज्ज्वल और अन्य बनाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और अन्य, (2005) 13 एससीसी 744**, इसी तरह की चुनौती उठाई गई थी जहां छात्र समुदाय ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में

प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में रैंकिंग को चुनौती दी गई थी, जिसमें यह शिकायत थी कि विभिन्न मुख्य उत्तर, जिसके आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था, स्वयं गलत थे और परिणामस्वरूप गलत और त्रुटिपूर्ण रैंकिंग तैयार की गई थी।

21. विशेषज्ञों की राय मांगी गई थी। विशेषज्ञों की राय सर्वसम्मति से थी कि विवादित प्रश्नों के मुख्य उत्तर गलत थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के पैरा 8 में नीचे दिए गए अनुसार देखा:-

“8. xxxxxxxxxxxx। यह संभव है कि छह प्रश्नों के सही मुख्य उत्तरों को फीड करके नया मूल्यांकन उन लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिन्होंने पहले से ही घोषित परिणामों और इन प्रश्नों के संबंध में गलत कुंजियों को फीड करके दी गई रैंकिंग के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर लिया है। हालांकि हम इस विचार के हैं कि विशेष रूप से अपीलकर्ताओं और सामान्य रूप से छात्र समुदाय, चाहे किसी ने अदालत का रुख किया हो या नहीं, को स्पष्ट रूप से गलत मुख्य उत्तरों के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए, लेकिन, साथ ही, यदि पहले परामर्श के परिणामस्वरूप पहले से ही दिए गए प्रवेशों को बाधित किया जाता है, तो यह संभव है कि पाठ्यक्रम की बहुत शुरुआत में देरी हो सकती है और पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 30-09-2005 से आगे बढ़ सकती है, जो नियमों में समय सारणी के अनुसार और मृदुल धर (नाबालिग) बनाम भारत संघ में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार कट-ऑफ तारीख है। इस विचार में, हम यह स्पष्ट करते हैं कि सही मुख्य उत्तरों को फीड करके कागजात का नया मूल्यांकन उन छात्रों को प्रभावित नहीं करेगा जिन्होंने पहले से ही घोषित परिणामों के संदर्भ में दी गई रैंकिंग के आधार पर पहले परामर्श के परिणामस्वरूप प्रवेश प्राप्त किया है।”

यह देखते हुए कि मामला छात्रों के प्रवेश से संबंधित था और कई प्रवेश पहले ही दिए जा चुके थे, उस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, यह स्पष्ट किया गया था कि सही उत्तरों को फीड करके कागजात का नया मूल्यांकन

उन छात्रों को प्रभावित नहीं करेगा जिन्होंने पहले से ही घोषित परिणामों के संदर्भ में दी गई रैंकिंग के आधार पर पहले परामर्श के परिणामस्वरूप प्रवेश प्राप्त किया है। हालांकि, विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा विवादित मुख्य उत्तरों की जांच के अभ्यास को बरकरार रखा गया था।

22. कानपुर विश्वविद्यालय, कुलपति और अन्य के माध्यम से (supra) के मामले में निर्णय पर भी भरोसा किया गया था, सिद्धांत को ऊपर की तरह दोहराया गया था और मनीष उज्ज्वल और अन्य (supra) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमेय कार्रवाई के पाठ्यक्रम को दोहराया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

"9. कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता में एक समान समस्या पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि यह माना जाता है कि कुंजी उत्तर सही हैं और संदेह की स्थिति में, अदालत निस्संदेह कुंजी उत्तर को प्राथमिकता देगी। इसी कारण से, हमने उन कुंजी उत्तरों का उल्लेख नहीं किया है जिनके संबंध में विशेषज्ञों के बीच राय के अंतर के परिणामस्वरूप संदेह है। जिन कुंजी उत्तरों के संबंध में मामला संदेह के दायरे से परे है, इस न्यायालय ने माना है कि छात्रों को एक ऐसे उत्तर नहीं देने के लिए दंडित करना अनुचित होगा जो कुंजी उत्तर के अनुरूप हो, यानी, एक ऐसे उत्तर के साथ जो गलत साबित होता है। उपरोक्त छह कुंजी उत्तरों के स्पष्ट रूप से गलत होने के बारे में कोई विवाद नहीं है और इस तथ्य पर विश्वविद्यालय के विद्वान वकील द्वारा सही ढंग से सवाल नहीं उठाया गया है। इस दृष्टिकोण में, छात्रों को विश्वविद्यालय की गलती और लापरवाही के लिए पीड़ित नहीं किया जा सकता है।

रण विजय सिंह और अन्य (supra) के मामले में एक बाद के निर्णय में, इस विषय पर कानून को नीचे दिए गए अनुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था:-

"30. इसलिए, इस विषय पर कानून काफी स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उजागर करने का प्रस्ताव करते हैं। वे हैं:

30.1 यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियमन एक अधिकार के रूप में उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन या जांच की अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकरण इसकी अनुमति दे सकता है;

30.2 यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियमन उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (इसे प्रतिबंधित करने से अलग) तो न्यायालय केवल तभी पुनः मूल्यांकन या जांच की अनुमति दे सकता है जब यह बहुत स्पष्ट रूप से, किसी भी "अनुमानित तर्क की प्रक्रिया या युक्तिकरण की एक प्रक्रिया" के बिना और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में यह प्रदर्शित किया जाता है कि एक भौतिक त्रुटि की गई है;

30.3 न्यायालय को किसी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन या जांच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए- इसके पास इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और अकादमिक मामलों को शिक्षाविदों के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा है;

30.4 न्यायालय को कुंजी उत्तरों की शुद्धता को मानना चाहिए और उस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए; और

30.5 संदेह की स्थिति में, लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को जाना चाहिए।

त्रिपुरा उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से (supra) के मामले में नवीनतम निर्णयों में से एक में, जबकि इस स्थापित कानूनी स्थिति को दोहराते और reaffirmed करते हुए कि पुनः मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, पुनः मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है या आदेश नहीं दिया जा सकता है, कानपुर विश्वविद्यालय, कुलपति और अन्य (supra), मनीष उज्ज्वल और अन्य (supra) और रण विजय सिंह और अन्य (supra) के मामलों में पहले देखे गए असाधारण प्रकृति के मामलों को ध्यान में रखा गया था और ऐसे असाधारण मामलों से निपटने के लिए अनुमेय कार्रवाई का पाठ्यक्रम, भले ही पुनः मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं था, विकसित किया गया था।

"19. हमने इस न्यायालय के निर्णयों को देखा है। निस्संदेह, एक तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्धारित किया है कि पुनः मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में पुनः मूल्यांकन का दावा करने या मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। निस्संदेह, कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में, impugned निर्णय में उच्च न्यायालय ने भी उक्त आधार पर

कार्यवाही की है। पहला प्रश्न जिसका हमें उत्तर देना होगा कि क्या किसी भी प्रावधान के अभाव के बावजूद, क्या न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पुनः मूल्यांकन का निर्देश देने की शक्ति से पूरी तरह से वंचित हैं? यह सच है कि रिट ऑफ मैडमस की मांग करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार के अस्तित्व और सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए उत्तर देने वाले प्रतिवादी के साथ संबंधित कर्तव्य पर आधारित है। इस प्रकार, अधिकार के रूप में, यह स्पष्ट है कि पहला प्रतिवादी पुनः मूल्यांकन की मांग करते हुए न तो रिट याचिका और न ही समीक्षा याचिका दायर कर सकता था।

20. हालांकि, सवाल उठता है कि क्या अगर पुनः मूल्यांकन की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो न्यायालय को किसी भी संदेह में छोड़ दें। कुछ परिस्थितियों में एक रिट आवेदक को एक गंभीर अन्याय हो सकता है। मामला तब उत्पन्न हो सकता है जब भले ही पुनः मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, यह पता चलता है कि सही उत्तर देने के बावजूद कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे एक ऐसे मामले तक सीमित होना चाहिए जहां उत्तर की शुद्धता के बारे में कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा, यदि कोई संदेह है, तो संदेह को उम्मीदवार के बजाय परीक्षा निकाय के पक्ष में हल किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 226 के तहत

व्यापक शक्ति तब भी उपलब्ध हो सकती है जब पुनः मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी स्थिति में जहां एक उम्मीदवार ने सही उत्तर दिया है और जिसके बारे में slightest manner of doubt नहीं हो सकता है, उसे गलत उत्तर देने वाला माना जाता है और परिणामस्वरूप उम्मीदवार को किसी भी अंक का हकदार नहीं पाया जाता है।

21. क्या रिट कोर्ट के पास मौजूद शक्ति के विशाल भंडार के बावजूद, यदि दूसरी परिस्थिति को रिट कोर्ट के समक्ष मौजूद होने के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तो क्या रिट कोर्ट असहाय हो सकता है? यह कहना एक बात है कि पुनः मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में उम्मीदवार को अधिकार के रूप में मूल्यांकन का अधिकार का दावा करने में सक्षम नहीं होगा और यह कहना दूसरी बात है कि किसी भी परिस्थिति में जहां पुनः मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, क्या रिट कोर्ट अपनी undisputed संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करेगा? हम दोहराते हैं कि स्थिति केवल दुर्लभ और असाधारण हो सकती है।

22. इसलिए, हम रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय से निकाले गए पैराग्राफ 30.2 में निष्कर्ष को केवल उपरोक्त आलोक में समझेंगे। हमने पहले ही देखा है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर में, एक दो न्यायाधीशों की पीठ ने पूरे केस कानून का सर्वेक्षण करने के

बाद पैराग्राफ 26 में यह भी समझा है कि कानून यह है कि किसी भी प्रावधान के अभाव में न्यायालय को आम तौर पर पुनः मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए।

23. xxxxxxxxx। यहां तक कि इस न्यायालय के रण विजय सिंह बनाम राहुल सिंह के निर्णय में भी, जो पहले प्रतिवादी के अनुसार उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का आधार बनता है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि न्यायालय पुनः मूल्यांकन की अनुमति दे सकता है, यदि यह बहुत स्पष्ट रूप से किसी भी अनुमानित तर्क की प्रक्रिया या युक्तिकरण की एक प्रक्रिया के बिना और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में एक भौतिक त्रुटि के कमीशन पर प्रदर्शित किया जाता है।
xxxxxxx।"

23. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और एक अन्य बनाम राहुल सिंह और एक अन्य (supra) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अकादमिक प्रकृति के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय की सीमा और शक्ति की जांच करते हुए, कानपुर विश्वविद्यालय, कुलपति और अन्य (supra) और रण विजय सिंह और अन्य (supra) के मामलों में निर्णयों पर भरोसा करते हुए, नीचे दिए गए अनुसार माना:

"9. कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता में, यह न्यायालय एक संयुक्त प्री-मेडिकल टेस्ट से संबंधित मामले से निपट रहा

था। यह स्वीकार किया गया कि परीक्षा सेटर ने स्वयं कुंजी उत्तर प्रदान किए थे और परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए कुंजी उत्तरों की शुद्धता को नियंत्रित या सत्यापित करने के लिए कोई समितियां नहीं थीं। इस न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि छात्रों ने साबित कर दिया था कि तीन कुंजी उत्तर गलत थे। न्यायालय के निम्नलिखित अवलोकन प्रासंगिक हैं:

"16.....हम सहमत हैं कि कुंजी उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए और इसे तर्क की एक अनुमानित प्रक्रिया द्वारा या युक्तिकरण की एक प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से गलत साबित किया जाना चाहिए, यानी, यह ऐसा होना चाहिए कि विशेष विषय में अच्छी तरह से वाकिफ पुरुषों का कोई भी उचित समूह इसे सही नहीं मानेगा।"

न्यायालय ने आगे निर्देश दिए लेकिन हम मुख्य रूप से एक से संबंधित हैं कि राज्य सरकार को पेपर सेटर्स द्वारा furnished कुंजी उत्तरों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

10. रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, इस न्यायालय ने न्यायिक घोषणाओं की एक श्रृंखला का जिक्र करने के बाद

कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया: (एससीसी पृष्ठ 368-69, पैरा 30)

“30. इस विषय पर कानून इसलिए काफी स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को उजागर करने का प्रस्ताव करते हैं। वे हैं:

30.1. यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियमन एक अधिकार के रूप में उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन या जांच की अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकरण इसकी अनुमति दे सकता है;

30.2. यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियमन उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (इसे प्रतिबंधित करने से अलग) तो न्यायालय केवल तभी पुनः मूल्यांकन या जांच की अनुमति दे सकता है जब यह बहुत स्पष्ट रूप से, किसी भी “अनुमानित तर्क की प्रक्रिया या युक्तिकरण की एक प्रक्रिया” के बिना और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में यह प्रदर्शित किया जाता है कि एक भौतिक त्रुटि की गई है;

30.3. न्यायालय को किसी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन या जांच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए—इसके

पास इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और अकादमिक मामलों को शिक्षाविदों के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा है;

30.4. न्यायालय को कुंजी उत्तरों की शुद्धता को मानना चाहिए और उस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए; और

30.5. संदेह की स्थिति में, लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को जाना चाहिए।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तब रण विजय सिंह और अन्य (*supra*) के मामले में पैरा 31 और 32 में किए गए अवलोकनों का उल्लेख किया ताकि यह प्रदर्शित और उजागर किया जा सके कि ऐसे मामलों में संवैधानिक न्यायालयों को संयम क्यों बरतना चाहिए और नीचे दिए गए अनुसार माना:

"11. हम पैरा 31 और 32 में निम्नलिखित अवलोकनों का भी उल्लेख कर सकते हैं जो दर्शाते हैं कि संवैधानिक न्यायालयों को ऐसे मामलों में संयम क्यों बरतना चाहिए: (रण विजय सिंह मामला, एससीसी पृष्ठ 369)

"31. हमारी ओर से हम यह जोड़ सकते हैं कि सहानुभूति या करुणा उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन को निर्देशित करने या निर्देशित नहीं करने के मामले में कोई भूमिका नहीं निभाती है। यदि परीक्षा प्राधिकरण द्वारा कोई त्रुटि की जाती है, तो उम्मीदवारों का पूरा निकाय पीड़ित होता है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया को केवल इसलिए पटरी से नहीं उतारा जाना चाहिए क्योंकि कुछ उम्मीदवार निराश या असंतुष्ट हैं या एक गलत प्रश्न या एक गलत उत्तर के कारण उन्हें कुछ अन्याय हुआ है। सभी उम्मीदवार समान रूप से पीड़ित होते हैं, हालांकि कुछ को अधिक पीड़ित होना पड़ सकता है लेकिन इससे बचा नहीं जा

सकता है क्योंकि गणितीय सटीकता हमेशा संभव नहीं होती है। इस न्यायालय ने एक गतिरोध से बाहर निकलने का एक तरीका दिखाया है - संदिग्ध या आपत्तिजनक प्रश्न को बाहर करना।

32. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद, जिनमें से कुछ पर ऊपर चर्चा की गई है, परीक्षाओं के परिणाम में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। यह परीक्षा अधिकारियों को एक unenviable स्थिति में रखता है जहां वे scrutiny में होते हैं और उम्मीदवार नहीं। इसके अतिरिक्त, एक massive और कभी-कभी लंबे समय तक चलने वाली परीक्षा अभ्यास अनिश्चितता की हवा के साथ समाप्त होता है। जबकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवार एक परीक्षा की तैयारी में tremendous प्रयास करते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए कि यहां तक कि परीक्षा प्राधिकरण भी एक परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए equally great efforts करते हैं। कार्य की विशालता बाद के चरण में कुछ चूक को प्रकट कर सकती है, लेकिन न्यायालय को उन उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों में हस्तक्षेप करने से पहले परीक्षा अधिकारियों द्वारा internal checks and balances को ध्यान में रखना चाहिए जिन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा में भाग लिया है और परीक्षा प्राधिकरणों को। वर्तमान अपीलें ऐसे हस्तक्षेप के परिणाम का एक classic example हैं जहां आठ साल बीत जाने के बाद भी परीक्षाओं के परिणाम की कोई निश्चितता नहीं है। परीक्षा अधिकारियों के अलावा, उम्मीदवार भी परीक्षा के परिणाम की निश्चितता या अन्यथा के बारे में सोच रहे हैं - क्या वे पास हुए हैं या नहीं; क्या उनके परिणाम को न्यायालय द्वारा अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाएगा; क्या उन्हें किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं; और क्या उन्हें भर्ती किया जाएगा या नहीं। यह असंतोषजनक स्थिति किसी के भी लाभ के लिए काम नहीं करती है और ऐसी अनिश्चितता की स्थिति उलझन को और बदतर बनाती है। इन सब का समग्र और बड़ा प्रभाव यह है कि सार्वजनिक हित पीड़ित होता है।"

अंत में, पहले के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को नीचे दिए गए अनुसार दोहराया गया:

"12. कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि उम्मीदवार पर यह दिखाने करने का दायित्व है कि कुंजी उत्तर गलत है बल्कि यह भी कि यह एक स्पष्ट गलती है जो पूरी तरह से स्पष्ट है और यह दिखाने के लिए किसी भी अनुमानित प्रक्रिया या तर्क की आवश्यकता नहीं है कि कुंजी उत्तर गलत है। संवैधानिक न्यायालयों को ऐसे मामलों में महान संयम का प्रयोग करना चाहिए और कुंजी उत्तरों की शुद्धता को चुनौती देने वाली दलील का मनोरंजन करने से अनिच्छुक होना चाहिए। कानपुर विश्वविद्यालय मामले में, न्यायालय ने एक प्रणाली की सिफारिश की:

- (1) नियंत्रण;
- (2) प्रश्नों में अस्पष्टता से बचना;
- (3) संदिग्ध प्रश्नों को बाहर करने के लिए तत्काल निर्णय लिए जाएं और ऐसे प्रश्नों को कोई अंक न दिया जाए।

13. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, पहले कुंजी उत्तरों की सूची प्रकाशित करने से पहले भी आयोग ने दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा कुंजी उत्तरों को नियंत्रित करवाया था। उसके बाद, आपत्तियां आमंत्रित की गईं और आपत्तियों को सत्यापित करने के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इस अभ्यास के बाद समिति ने सिफारिश की कि 5 प्रश्नों को हटा दिया जाए और 2 प्रश्नों में, कुंजी उत्तर बदल दिए जाएं। यह माना जा सकता है कि इन समितियों में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शामिल थे जिनके लिए परीक्षार्थियों का परीक्षण किया गया था। न्यायाधीश अकादमिक मामलों में विशेषज्ञों की भूमिका नहीं ले सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। जब तक, उम्मीदवार यह प्रदर्शित नहीं करता है कि कुंजी उत्तर इसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से गलत हैं, न्यायालय अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के

pros and cons का वजन नहीं कर सकते हैं और फिर यह निष्कर्ष पर नहीं आ सकते हैं कि कौन सा उत्तर बेहतर या अधिक सही है।"

इसके अलावा, यह देखा गया कि चुनौती तीन प्रश्नों से संबंधित थी जिन्होंने तर्क की एक लंबी प्रक्रिया को नोट किया और यह देखा गया कि आयोग द्वारा लिया गया रुख कुछ पाठ्यपुस्तकों द्वारा समर्थित था। उस तथ्यात्मक परिदृश्य में, यह माना गया कि परस्पर विरोधी विचारों के मामले में, न्यायालय को विशेषज्ञों की राय का पालन करना चाहिए। इसे नीचे दिए गए अनुसार माना गया:

"14. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि सभी तीन प्रश्नों को तर्क की एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता थी और उच्च न्यायालय ने स्वयं यह देखा है कि आयोग का रुख भी कुछ पाठ्यपुस्तकों द्वारा समर्थित है। जब परस्पर विरोधी विचार होते हैं, तो न्यायालय को विशेषज्ञों की राय का पालन करना चाहिए। न्यायाधीश सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ नहीं होते हैं और नहीं हो सकते हैं और इसलिए, उन्हें महान संयम का प्रयोग करना चाहिए और विशेषज्ञों की राय को परेशान करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को नहीं लांघना चाहिए।"

24. रिचेल और अन्य (supra) के मामले में, समय-समय पर बताए गए और दोहराए गए सिद्धांतों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फिर से पुष्टि की गई थी, जबकि प्राप्त आपत्तियों को ध्यान में रखने के बाद विशेषज्ञ समिति द्वारा तय किए गए अंतिम कुंजी उत्तरों की शुद्धता से निपटते हुए। कानपुर विश्वविद्यालय, कुलपति और अन्य (supra), मनीष उज्ज्वल और अन्य (supra) के मामलों में निर्णयों पर भरोसा रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग

और अन्य (2005) 13 एससीसी 749 और राजेश कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2013) 4 एससीसी 690 के मामलों में अपने पहले के निर्णयों पर भी भरोसा किया और नीचे दिए गए अनुसार माना:

“17. इसी तरह के प्रभाव के लिए, इस न्यायालय ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग में, विश्वविद्यालय को सीबीएसई द्वारा प्रदान किए गए कुंजी उत्तरों के संदर्भ में 8 प्रश्नों के उत्तरों का पुनः मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था। इस न्यायालय ने विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम को भी अस्वीकार कर दिया था जिसने सभी छात्रों को अंक दिए थे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, भले ही किसी ने प्रश्नों का उत्तर दिया हो या नहीं।

18. एक और निर्णय जिसका उल्लेख किया गया है वह राजेश कुमार बनाम बिहार राज्य है, जहां इस न्यायालय को गलत उत्तर कुंजी का उपयोग करके त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन से संबंधित मामले पर विचार करने का अवसर मिला। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों के खिलाफ आवेदन आमंत्रित किए। चयन प्रक्रिया में एक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा शामिल थी। असफल उम्मीदवारों ने चयन को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने विशेषज्ञों को "मॉडल उत्तर कुंजी" संदर्भित की। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर, एकल न्यायाधीश ने माना कि 100 में से 41 मॉडल उत्तर गलत थे। एकल न्यायाधीश ने माना कि पूरी परीक्षा रद्द करने योग्य थी और इसी तरह उस पर किए गए नियुक्तियों को भी। कुछ उम्मीदवारों द्वारा letters patent appeal दायर की गई थी जिसे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया और घोषित किया कि पूरी परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 19 में माना है: (एससीसी पृष्ठ 697)

"19. श्री राव द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ योग्यता के बिना नहीं हैं। उत्तर कुंजी में दोष की प्रकृति को देखते हुए scripts के मूल्यांकन को सही करने का सबसे प्राकृतिक और तार्किक तरीका कुंजी को सही करना और उसके आधार पर उत्तर scripts का पुनः मूल्यांकन करना था। ऐसी परिस्थितियों में, आयोग द्वारा एक नई परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का कोई compelling कारण नहीं था, खासकर जब किसी भी कदाचार, धोखाधड़ी या भ्रष्ट motives के बारे में कोई आरोप नहीं था जो पहले की परीक्षा को रद्द कर सकता था ताकि सभी संबंधितों द्वारा एक नए प्रयास की मांग की जा सके। सही कुंजी के संदर्भ में उत्तर scripts का पुनः मूल्यांकन करने की प्रक्रिया भी कम महंगी होगी, इसके अलावा quicker भी होगी। यह प्रक्रिया किसी भी उम्मीदवार को पहले आयोजित परीक्षा और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार आयोजित की गई परीक्षा के बीच समय के अंतराल के कारण कोई अनुचित लाभ नहीं देगी। यह कहना पर्याप्त है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पुनः मूल्यांकन एक बेहतर विकल्प था और है।"

यह मानते हुए कि पेपर-सेटर या परीक्षा निकाय द्वारा तैयार किए गए कुंजी उत्तरों को उचित विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया माना जाता है, कुंजी उत्तरों का प्रकाशन और परीक्षा निकाय द्वारा विचार किए जाने के लिए आपत्तियों को प्राप्त करके उत्तरों की शुद्धता का आकलन करने का अवसर देना पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए एक कदम माना गया था। इस प्रकार यह देखा गया:

"19. पेपर-सेटर या परीक्षा निकाय द्वारा तैयार किए गए कुंजी उत्तरों को उचित विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया माना जाता है। गलती करना मानव है। ऐसे कई कारक हैं जो गलत कुंजी उत्तर तैयार करने के कारण हो सकते हैं। कुंजी उत्तरों का प्रकाशन पारदर्शिता प्राप्त करने और उम्मीदवारों को उनके उत्तरों की शुद्धता का आकलन करने का अवसर देने के लिए एक

कदम है। परीक्षा निकाय द्वारा अपलोड किए गए कुंजी उत्तरों के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने का अवसर प्रक्रिया में निष्पक्षता और पूर्णता प्राप्त करने का एक कदम है। कुंजी उत्तरों पर आपत्तियों की जांच विशेषज्ञों द्वारा की जानी है और उसके बाद, यदि कोई हो, तो सुधारात्मक उपाय परीक्षा निकाय द्वारा किए जाने चाहिए। वर्तमान मामले में, हमने नोट किया है कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद आयोग द्वारा अंतिम कुंजी उत्तर प्रकाशित किए गए थे, जिसके बाद आयोग द्वारा अपनाए गए कुंजी उत्तरों की शुद्धता को चुनौती देते हुए कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञों के विचारों को स्वीकार करते हुए चुनौती को खारिज कर दिया। उम्मीदवार अभी भी असंतुष्ट हैं, उन्होंने इन अपीलों को दायर करके इस न्यायालय में आए हैं।"

25. उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों और स्थापित कानूनी स्थिति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य बनाम अरुण कुमार और अन्य, (2020) 6 एससीसी 362 और विकेश कुमार गुप्ता और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2021) 2 एससीसी 309 के मामलों में हाल के न्यायिक घोषणाओं में दोहराया। विकेश कुमार गुप्ता और एक अन्य (supra) के मामले में, एक बार फिर रण विजय सिंह और अन्य (supra) के मामले में निर्णय का संदर्भ था। यह देखा गया था:

"16. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून के मद्देनजर, डिवीजन बेंच के लिए 12.03.2019 के अपने फैसले में विशेषज्ञ समिति से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रश्नों और उत्तर कुंजी की शुद्धता की जांच करना खुला नहीं था। रिचेल बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग पर अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया था। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति की राय प्राप्त करने के बाद ही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था, लेकिन स्वयं प्रश्नों और उत्तरों की शुद्धता में

प्रवेश नहीं किया था। इसलिए, उक्त निर्णय इस मामले में विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं है।"

26. उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, यह एक स्थापित कानूनी स्थिति के रूप में उभरता है कि हालांकि किसी भी नियम/योजना के अभाव में पुनः मूल्यांकन कानून में अनुमेय नहीं है, जो परीक्षा को नियंत्रित करता है, असाधारण मामलों में, जहाँ उत्तर स्पष्ट रूप से गलत पाए जाते हैं, उम्मीदवारों को हुए अन्याय को पूर्ववत करना होगा। ऊपर संदर्भित कई मामलों में अपनाए गए कार्रवाई का तरीका, जिसे न्यायालयों द्वारा अनुमोदित किया गया था, वह यह था कि कुंजी उत्तरों या विवादित प्रश्नों के संबंध में शिकायतों की जांच विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जानी है और यदि विशेषज्ञ समिति की राय दर्शाती है कि मॉडल उत्तर स्पष्ट रूप से गलत हैं और कुछ अन्य विकल्प सही हैं, तो नीचे दिए गए उत्तरों को सही कुंजी के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जहाँ प्रश्न स्वयं अस्पष्ट और गलत थे या जहाँ दिए गए विकल्पों में से कई सही उत्तरों का मामला था, वहाँ प्रश्नों को हटा दिया जाना आवश्यक है और अभ्यर्थियों का मूल्यांकन उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर किया जाना चाहिए। हटाए जाने के बाद भी शेष प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। न्यायिक समीक्षा का दायरा उन असाधारण मामलों तक सीमित है जहाँ न्यायालय पाता है कि मॉडल उत्तर कुंजियाँ तर्क की अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया के बिना, पहली नज़र में ही स्पष्ट रूप से गलत हैं।

27. अब हम उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में मामले के तथ्यों की जांच करेंगे।

28. अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित सामग्रियों पर भरोसा किया है:-

(i) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, टोडा रायसिंह का दिनांक 04.05.2022 का पत्र, जो एक कुशल भारद्वाज के आवेदन पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करता है कि संत पीपा जी की गुफा बुद्ध सागर तालाब, टोडा रायसिंह की पहाड़ियों पर स्थित है।

(ii) उपाध्यक्ष, नगर पालिका, टोडा रायसिंह, टोंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो प्रमाणित करता है कि प्राधिकरण के समक्ष रखी गई तस्वीरों में दर्शाया गया है कि संत पीपा जी की गुफा टोडा रायसिंह, टोंक में बुद्ध सागर तालाब की पहाड़ियों पर स्थित है।

(iii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर सर्कल की वेबसाइट सामग्री, जिसमें दर्शाया गया है कि पीपा जी मंदिर टोडा रायसिंह में स्थित है।

(iv) डॉ. हुकम चंद जैन और डॉ. नारायण माली द्वारा लिखित राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लोपीडिया नामक पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ 532, जिस पर विशेषज्ञ समिति ने भरोसा किया है, स्वयं यह उल्लेख करता है कि पीपा जी की गुफा टोडा रायसिंह में स्थित है।

(v) ललित शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थान राजर्षि संत पीपाजी में, यह उल्लेख किया गया है कि संत पीपा जी ने टोडा नगर में बुद्ध सागर सरोवर हिल्स में एक गुफा का निर्माण किया था।

(vi) 2008 में अधिशासी अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए आयोजित एक पहले की परीक्षा में भी, सही उत्तर कुंजी को "टोडा" के रूप में स्वीकार किया गया था, न कि "गागरोन" के रूप में, उस स्थान के रूप में जहां संत पीपा जी की गुफा स्थित है।

29. माननीय एकल न्यायाधीश ने विशेषज्ञ समिति के निर्णय को ध्यान में रखते हुए बरकरार रखा कि विशेषज्ञ समिति ने उसके पास उपलब्ध सामग्री पर उचित विचार करने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सही उत्तर कुंजी

विकल्प (डी) यानी गागरोन होगी, उस स्थान के रूप में जहां संत पीपा जी की गुफा स्थित है।

30. प्रश्न संख्या 135 के सही उत्तर कुंजी पर निर्णय के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट हमें एक सीलबंद लिफाफे में रखी गई है। समिति के समक्ष निम्नलिखित आपत्ति रखी गई थी:-

"विकल्प बी गलत और विकल्प डी सही है। डॉ. हुकम चंद जैन और डॉ. नारायण लाल माली के राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा राजस्थान का इतिहास संस्कृति परम्परा एवं विरासत संस्करण 2020 पृष्ठ संख्या 373 और क्षितिज कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पृष्ठ संख्या 102 के अनुसार कृपया इस प्रश्न पर विचार करें और मुझे बोनस अंक दें।"

समिति ने नीचे दिए गए अनुसार निर्णय लिया:-

"आपत्ति स्वीकार की गई" - "सबूत संलग्न - राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लोपीडिया, डॉ. हुकम चंद जैन, डॉ. नारायण माली - पृष्ठ 196"

31. समिति ने तदनुसार आपत्ति स्वीकार कर ली और विकल्प "(डी) गागरोन" को सही उत्तर कुंजी के रूप में अंतिम रूप दिया। विचार-विमर्श चार्ट के अंतिम कॉलम से पता चलता है कि समिति ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए डॉ. हुकम चंद जैन और डॉ. नारायण माली (पृष्ठ-196) द्वारा लिखित राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लोपीडिया की सामग्री पर

भरोसा किया है। सीलबंद लिफाफे में विशेषज्ञ समिति द्वारा भरोसा किए गए उपरोक्त पाठ/एनसाइक्लोपीडिया के प्रासंगिक अंश शामिल हैं। प्रासंगिक सामग्री नीचे दिए गए अनुसार है:-

"संत पीपा गागरोन के खींची राजपूत राजा थे। उनका राज्यकाल 1362 से 1377 ईस्वी तक माना जाता है। बचपन से ही इन्हें ईश्वर भक्ति में गहरी रुचि थी। संत पीपा राजकाज छोड़कर बनारस चले गए और वहाँ पर रामानंद के शिष्य बन गए। रामानंद ने पीपा को माया छोड़कर भक्ति करने और साधु-संतों की सेवा करने का उपदेश दिया। संत पीपा गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगे। संत पीपा के विशेष अनुरोध पर कबीर के साथ रामानंद गागरोन आए। कुछ समय तक संत पीपा अपने गुरु के साथ रहे। संत पीपा घूम-फिरकर पुनः गागरोन आए और एक गुफा में रहने लगे। ये उच्च कोटि के संत थे। संत पीपा ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबरों, छुआछूत आदि का विरोध किया। संत पीपा मानते थे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं।"

32. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि जब विभिन्न ग्रंथों और अन्य सामग्रियों से कई सामग्री आपत्तियों के साथ विशेषज्ञ समिति के विचार के लिए रखी गई, तो विशेषज्ञ समिति ने अपनी बुद्धिमत्ता में, जिसमें निस्संदेह विषय के विशेषज्ञ शामिल हैं, एक निर्णय लिया है कि विकल्प "(डी) गागरोन" को उस स्थान के रूप में सही उत्तर कुंजी के रूप में माना जाना चाहिए जहां गुफा स्थित है। आश्चर्यजनक रूप से, उसी पुस्तक (राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लोपीडिया) के पृष्ठ 532 पर, यह नीचे दिए गए अनुसार कहा गया है:-

“ऐतिहासिक कस्बा टोडा रायसिंह में बुद्ध सागर तालाब,
पीपाजी की गुफा, सातोलवा तालाब, लल्ला पठान का किला,
हाड़ी रानी का कुंड तथा दो कलात्मक बावडियां दर्शनीय हैं।”

33. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने भी हमारे समक्ष एक और पाठ्यपुस्तक रखी है, जिसका नाम राजस्थान में भक्ति आंदोलन है, जिसे प्रोफेसर पेमाराम द्वारा लिखा गया है और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया है। उस पाठ्यपुस्तक में भी, संत पीपा के संबंध में विवरण इस आशय के दिए गए हैं कि संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी (विक्रम संवत् 1482) में हुआ था और वे राजपूताना के गागरोन राज्य के एक *खींची राजपूत शासक* थे। पाठ में संत पीपा द्वारा यात्रा किए गए विभिन्न स्थानों के बारे में further details दिए गए हैं, और यह कि संत पीपा गागरोन वापस आए और फिर से चले गए। इसमें यह भी उल्लेख है कि अपनी कई स्थानों की यात्रा के दौरान, संत पीपा टोडा भी गए और अंत में गागरोन वापस आए और *आहू और कालीसिंध* नदियों के संगम पर स्थित एक गुफा में रहने लगे और वह स्थान उनके मंदिर, निवास और गुफा के लिए प्रसिद्ध है।

34. यह न्यायालय विशेषज्ञ समिति द्वारा लिए गए निर्णय से अलग निर्णय पर पहुंचने के लिए विशेषज्ञ की भूमिका नहीं लेगा, खासकर जब विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया गया निर्णय एक प्रामाणिक पाठ पर आधारित है, जिस पर न केवल अपीलकर्ता बल्कि प्रतिवादी, दोनों भरोसा करते हैं। हालांकि, यह काफी स्पष्ट है कि जिस स्थान पर संत पीपा की गुफा स्थित है, वह एक ऐतिहासिक तथ्य है और इस बात पर कोई सर्वसम्मति नहीं है कि वह गुफा कहाँ स्थित है। निस्संदेह, कुछ ग्रंथ जो अपीलकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, वे दर्शाते हैं कि संत पीपा की गुफा टोडा में

स्थित है, उसी समय डॉ. हुकम चंद जैन और डॉ. नारायण माली द्वारा लिखित पुस्तक "राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति एनसाइक्लोपीडिया" का अन्य प्रामाणिक पाठ भी यह खुलासा करता है कि संत पीपा गागरोन में एक गुफा में रुके थे।

35. प्रश्न संख्या 135 से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य की शुद्धता में प्रवेश किए बिना, जो अनिवार्य रूप से केवल विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाने वाला मामला है और न्यायालय द्वारा नहीं, खासकर जब यह 1362 से 1377 की अवधि के दौरान संत पीपा के आंदोलन और रहने के संबंध में एक ऐतिहासिक तथ्य है, हम इन ग्रंथों के एक bare reading से पाते हैं कि संत पीपा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए और वे न केवल टोडा में, बल्कि गागरोन में भी रहे। हालांकि, विभिन्न ग्रंथों में दी गई उपरोक्त प्रासंगिक जानकारी के आधार पर, जिनका दोनों पक्षों ने उल्लेख किया है, विषय के विशेषज्ञों ने यह तय किया कि विकल्प "(डी) गागरोन" को सही उत्तर कुंजी के रूप में माना जाना चाहिए।

36. हमारे विचार से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में, जिनका यहां ऊपर उल्लेख किया गया है, रिट न्यायालय इस प्रश्न में आगे जाने में असमर्थ पाता है और जांच यहीं रुकनी चाहिए। ऊपर संदर्भित प्रसिद्ध निर्णयों में, यह अधिकारपूर्वक निर्धारित किया गया है कि उत्तर कुंजी की शुद्धता के संबंध में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप केवल तभी अनुमेय होगा, जब यह बहुत स्पष्ट रूप से, किसी भी अनुमानित तर्क की प्रक्रिया या युक्तिकरण की एक प्रक्रिया के बिना और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में यह प्रदर्शित किया जाता है कि एक भौतिक त्रुटि की गई है। यह भी माना गया है कि न्यायालय को किसी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन या जांच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए

क्योंकि उसके पास इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और अकादमिक मामलों को शिक्षाविदों के लिए छोड़ना सबसे अच्छा है। इसके अलावा, यह भी एक स्पष्ट कानूनी स्थिति के रूप में स्थापित किया गया है कि न्यायालय को कुंजी उत्तरों की शुद्धता को मानना चाहिए और उस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए और संदेह की स्थिति में, लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को जाना चाहिए।

37. उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, सर्वोत्तम रूप से, इसे संदेह का मामला कहा जा सकता है और, इसलिए, लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को जाना चाहिए।

38. उपरोक्त चर्चा के परिणाम के रूप में, हम माननीय एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं।

39. दोनों अपीलें तदनुसार खारिज की जाती हैं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, भी खारिज किया जाता है।

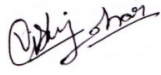
40. इस आदेश की एक प्रति संबंधित फ़ाइल में रखी जाए।

(शुभा मेहता), जे

(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे

कमलेश कुमार /1

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़